AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

वर्तमान परीक्षा प्रणाली व परीक्षा में सुधारः एक अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. सुधीर कुमार सिंह
सहायक प्रध्यापक, बी.एड. विभाग
महाराणा प्रताप राजकीय पी.जी. कॉलेज
हरदोई, उत्तरप्रदेश, भारत

शोध सार

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परीक्षा प्रणाली की सहायता से संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया की सफलता का आंकलन किया जाता है, जिसके आधार पर वास्तविक उपलब्धि को तय किया जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में यह विश्लेषण किया जायेगा की क्या वर्तमान में प्रचलित परीक्षा प्रणाली अध्यापक के शिक्षण की प्रभावशीलता , छात्रों की शैक्षिक प्रगति एवं प्रशासक वर्ग के शैक्षिक निवेश को कितना न्याय संगत ढंग से आकलित कर पा रही है। परीक्षा प्रणाली के आधार पर विद्यार्थियों के भविष्य का निर्णय होता है, प्राध्यापक अपनी शैक्षिक तकनीक की प्रभावशीलता सही आंकलन कर पाते है। अतः वर्तमान परीक्षा प्रणाली इन उद्देश्यों को पूरा करने में कितना सफल है एवं इसमें क्या सुधार हो सकता है इस शोध पत्र के प्रमुख विषय होंगे।

मुख्य शब्द

परीक्षा, अधिगम, शिक्षण, अध्यापक, प्रणाली, विवेचन.

प्रस्तावना

वास्तव में परीक्षाएं उतनी प्राचीन है जितना कि मानव ज्ञान भंडार, किसी न किसी रूप में परीक्षा मनुष्य के जीवन काल में हर समय होती रहती है, कभी वह औपचारिक रूप से तो कभी अनौपचारिक रूप से तो कभी मौखिक रूप से तो कभी लिखित रूप मे परीक्षा जीवन का मूल तथ्य है। परीक्षाओं मे मुख्य रूप से दो पक्ष अध्यापक एवं छात्र को इस प्रकार से क्रियाशील बनाती हैं कि छात्र अधिक से अधिक अध्ययन कर सके तथा अध्यापक इस कार्य में विद्यार्थी की अधिक से अधिक सहायता, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन कर सके।

भारतीय परीक्षा प्रणाली मूल रूप से अंक प्रधान है अर्थात् परीक्षा का मूल्यांकन अंकों के आधार पर होता है अंकों के आधार पर विद्यार्थियों की एक श्रेणी तय की जाती है ज्यादा अंक पाने वाला अधिक प्रतिभाशाली एवं कम अंक पाने वाला कम प्रतिभाशाली होता है। सामान्यतः शैक्षिक सत्र के समापन पर परीक्षाओं का आयोजन होता है यही परीक्षाएं उसके आगे के भविष्य को तय करती है। विचारणीय यह हैं कि, क्या परीक्षाओं के माध्यम से छात्र एवं अध्यापक का निरपेक्ष मूल्यांकन हो पा रहा कि नही और प्राप्त अंक कितने निरपेक्ष है जिसके आधार पर विद्यार्थी के भविष्य का निर्णय उसके अभिभावक ले सके तथा इस आधार पर शैक्षिक नीतियों का निर्माण कैसे हो। आज हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली अंक प्रधान है। अधिकतम अंक प्राप्त करने की

एक अंधी प्रतियोगिता हैं जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी संसाधनों का प्रयोग विद्यार्थी तथा अभिभावक द्वारा किया जाता है।

कुछ तथ्यों पर विचार करना समीचीन होगा कि, प्रचलित शिक्षा प्रणाली कितनी निरपेक्षता के साथ विद्यार्थी का मूल्यांकन कर पाती है समय के साथ परीक्षा प्रणाली और उसके स्वरूप में बदलाव होता गया, आज हम NEP 2020 से आच्छादित है। वैदिक काल से लेकर NEP 2020 की परीक्षा पद्धति का मूल्यांकन किया जाए तो एक उपयुक्त एवं यथार्थवादी परीक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. पूर्व में प्रचलित परीक्षा प्रणाली का अध्ययन करना।
2. परीक्षा के विविध आयामों का विश्लेषण करना।
3. वर्तमान में प्रचलित परीक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना।

विवेचना

वर्तमान प्रचलित परीक्षा प्रणाली की विवेचना से पूर्व भारत में विभिन्न कालों यथा वैदिक काल, बौद्धकाल, मध्यकाल, ब्रिटिश भारत एवं स्वतंत्रता के बाद विभिन्न आयोगों की संस्तुतियों पर चर्चा करना नितांत आवश्यक है।

प्राचीन भारत में प्रचलित परीक्षा प्रणाली

प्राचीन भारत में शिक्षा मुख्य रूप से वैदिक काल,एवं बौद्ध काल में काफी विकसित स्वरुप में थी। प्राचीन भारत में अनेकों शिक्षा के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भारत में स्थापित थे, जैसेः नालंदा, तक्षशिला, बलभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, जगदल्ल में शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली की स्पष्ट झलक मिलती है। वैदिक काल में शिक्षण प्रकिया का स्वरुप काफी विकसित और यथार्थवादी था।

वैदिक काल में परीक्षा तो पूर्णतया मौखिक ही थी, लेकिन शिक्षण सत्रों का उल्लेख मिलता है, वैदिक काल के शिक्षण सत्र का विवरण इस तालिका से समझा जा सकता है।

शिक्षण–सत्र की अवधि	शिक्षण सत्र का माह	संस्कार	परीक्षा
5 से 6 माह	सत्रारंभ– श्रावण मास की पूर्णिमा (जुलाई–अगस्त)	उपाकर्म	नित्य/मौखिक
	समापन–माघ मास की पूर्णिमा (जनवरी–फरवरी)	उत्सर्जन	

वैदिक काल के शिक्षण सत्र का विश्लेषण किया जाए तो भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप परीक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया था, जो उपयुक्त एवं न्यायसंगत था।

बौद्धकाल में परीक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से बौद्ध क्रिया–कलापों से संबंधित होती थी। प्रबज्जा एवं उपसंपदा संस्कार महत्वपूर्ण थे, शिक्षण विधि पूर्ण रूप से मौखिक थी, प्रवचन, भाषण, प्रश्नोत्तर पर ज्यादा बल दिया जाता था। ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली, जिससे आधुनिक भारतीय शिक्षा की नीव पड़ी। लगभग सभी आयोगों द्वारा आतंरिक एवं वार्षिक परीक्षा पर जोर दिया गया परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं उपाधियाँ प्राप्त करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बन गया। 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी जिनका मुख्य कार्य परीक्षा को सम्पादित करना एवं उपाधियाँ प्रदान करना था। राधाकृष्णन आयोग ने कहा की परीक्षा कोर्स के अंत में होनी चाहिए,कोठारी कमीशन ने भी परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए अनेकों सुझाव दियें, साथ ही सतत् एवं आतंरिक परीक्षा पर ज्यादा जोर दिया।

सारांश रूप में देखा जाए तो पूर्व में जितने भी आयोग स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता बाद बनाए गए उन्होंने ज्यादातर वार्षिक परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन पर जोर दिया है। कुल मिलाकर पूर्व में सतत मूल्यांकन और वार्षिक परीक्षा प्रणाली का मिला–जुला रूप प्रचलित था।

वर्तमान प्रचलित सेमेस्टर परीक्षा की व्यवहारिक समस्याओं का स्वरूप

वर्तमान में प्रचलित सेमेस्टर परीक्षा सैद्धांतिक रूप से तो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित परीक्षा प्रणाली परिलक्षित होती हैं,लेकिन इसके क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएं परिलक्षित होती हैं जिसका विवरण बिंदुवार प्रस्तुत हैः

- NEP 2020 के अनुरूप संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था का न होना।
- भारत की ग्रामीण पृष्ठभूमि एवं उसकी आवश्यकता का सही आंकलन ना कर पाना।
- सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को लागू करने में महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की राय का यथार्थ विश्लेषण ना कर पाना।
- भारत की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सही विश्लेषण ना होना।
- शैक्षिक संस्थानों के क्रियान्वयन मे सभी चरणों जैसे प्रवेश, प्रक्रिया, परीक्षा ,परिणाम में सामंजस्य ना होना।
- विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा की योजना बनाते समय महाविद्यालय की समस्याओं का सही ढंग से संज्ञान न लेना और ना निराकरण करना।
- ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षाविदों में उदासीनता का भाव।
- पाठ्यक्रम का निर्धारण सही ढंग से ना कर पाना।
- भारत की प्राचीन शिक्षा नीतियों का अनुकरण ना करना।
- सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली का परीक्षा प्रधान अधिक होना।
- प्राचीन भारतीय मूल्यांकन पद्धति की उपेक्षा करना।
- सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में छात्र पूरे वर्ष परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं ,जबकि पाठ्यक्रम को पूरा करने में व्यावहारिक समस्याएं आती हैं।
- विश्वविद्यालय का महाविद्यालय में अनावश्यक हस्तक्षेप।
- सरकार का गैर पाठ्यक्रम क्रियाकलापों पर ज्यादा जोर।
- शिक्षकों का पर्याप्त और वास्तविक प्रशिक्षण ना होना।
- समय सारणी को निर्धारित करने की व्यवहारिक समस्या
- बार–बार यूजीसी द्वारा नियमों में बदलाव।

निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति 2020 का ज्यादा जोर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर है जबकि सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में शिक्षक का पक्ष सबसे ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। विश्वविद्यालय भी समय से परीक्षा, और परिणाम जारी करना ही अपना उत्तरदायित्व समझ रहे हैं जिसका मूल्यांकन भी अयोग्य शिक्षकों द्वारा अत्यंत शीघ्रता से कराया जाता है, जबकि वार्षिक परीक्षा प्रणाली में शिक्षण पद्धति की प्रक्रियाओं प्रवेश, परीक्षा, परिणाम और शिक्षण में एक संतुलन होता हैं।

सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव

पूर्व में वर्णित व्यावहारिक समस्याओं की विश्लेषण के आधार पर सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में ,सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैंः

1. शिक्षण कार्य भले ही सेमेस्टर पद्धति पर हो, लेकिन परीक्षा का स्वरूप वार्षिक हो–राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य विजन यही है कि भारतीय मूल्यों से विकसित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। लेकिन वर्तमान सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली केवल परीक्षा प्रधान होती जा रही है, जिससे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य

लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यदि परीक्षा का स्वरूप वार्षिक होगा तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम समय से पूरे हो पाएंगे और पाठय सहगामी क्रियाकलापों का सही ढंग से क्रियान्वयन हो पाएगा और छात्रों का समय, धन, और परिश्रम तीनों का सही सदुपयोग हो पाएगा।

2. **आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जायः** यदि मूल्यांकन प्रणाली में आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली को प्रभावशाली ,वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी बना दिया जाए, ज्यादा वस्तुनिष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे और विद्यार्थी का सही मूल्यांकन हो पाएगा।
3. **शिक्षकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएः** प्रशिक्षण में हमेशा ऑफलाइन पद्धति को अपनाया जाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण में मुख्य रूप से तीन बातों को सम्मिलित किया जाना नितांत आवश्यक है, प्रथम की उनको पूरी तरह से तकनीकी दक्ष बनाया जाए, द्वितीय महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकों भारत के ग्रामीण पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी दी जाय, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसके अंदर अपनी शैक्षिक सेवा के प्रति उच्च समर्पण का भाव पैदा करने का प्रयास किया जाए। भारत में कर्तव्य, पथभ्रष्ट शिक्षको की संख्या लगातार बढ़ रही हैं।
4. **हर जिले में एक उपस्थित अधिकारी की नियुक्ति होः** पाठ्यक्रम समय से पूरा ना हो पाना एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका मूल कारण शिक्षको का अपने उत्तरदायित्वो के प्रति उदासीन होना, विद्यालय समय से न आना, आदि। प्राचार्य, प्रधानाचार्य, अध्यापकों, कर्मचारी की उपस्थिति प्रतिदिन वस्तुनिष्ट ढंग से समीक्षा करने के लिए एक उपस्थित अधिकारी होना चाहिए जिसके पास पर्याप्त संवैधानिक अधिकार हो और लापरवाह, कर्तव्यों के प्रति उदासीन शिक्षकों के प्रति वह कठोर कार्रवाई कर सके।
5. **आवश्यकता अनुसार सायंकालीन कक्षाओं का प्रबंध होंः** सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या यही है कि समय से पाठ्यक्रम नहीं पूरा हो पता है। इसका एक समाधान हो सकता है कि आवश्यकता अनुसार सायंकालीन कक्षाओं का प्रबंध हो ताकि समय पर पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सके।
6. विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, परीक्षा नियंत्रक आदि की नियुक्ति सीधी खुली प्रतियोगिता के माध्यम से हो। शैक्षिक संवर्ग की समस्त नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होनी चाहिए। साक्षात्कार के अंकों को न्यूनतम महत्व दिया जाए। इन नियुक्तियों में ग्रामीण पृष्ठभूमि और सरकारी विद्यालय में पढ़े छात्रों को वरीयता दी जाए क्योंकि वास्तविक समस्या को भावनात्मक रूप से वही समझ सकता हैं जो उस पृष्ठिभूमि में खुद रहा हो।
7. **विश्वविद्यालय के लिए अलग शैक्षिक कैलेंडर हो एवं महाविद्यालय के लिए अलग शैक्षिक कैलेंडर होना चाहिएः** विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि और समस्या अलग होती है महाविद्यालय की पृष्ठभूमि और समस्या अलग होती है इसलिए दोनों का शैक्षिक कैलेंडर अलग–अलग निर्मित किया जाना चाहिए।
8. परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय से ही संपादित होना चाहिए। निरपेक्ष व्यवस्था के संचालन हेतु केवल राजकीय, अनुदानित महाविद्यालय,को परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन का उत्तरदायित्व देना चाहिए।

निष्कर्ष

निश्चित रूप से किसी राष्ट्र का एकमात्र उद्देश्य उसके नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हैं जो समसामयिक हो एवं राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ बने, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रतिस्थापित की गई व परीक्षा के लिए सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को अपनाया गया।

निश्चित रूप से सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली अपने आप में पूर्ण और अच्छी है लेकिन इसको लागू करने में जो व्यावहारिक समस्याएं आती हैं उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। किसी भी परीक्षा प्रणाली के चार महत्वपूर्ण चार भाग होते प्रवेश, शिक्षण प्रक्रिया, परीक्षा और परिणाम। इनकी अंतःक्रिया ही एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सही

आउटपुट हो सकता है जो एक सुयोग्य और उत्तम नागरिक का निर्माण कर सकती हैं, यदि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वास्तविक विश्लेषण किया जाए तो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा मूल रूप से चार प्रक्रियाएं आयोजित की जाती है। हर सेमेस्टर में प्रथम प्रवेश प्रक्रिया द्वितीय शिक्षण कार्य तृतीय परीक्षा संबंधी कार्य और चतुर्थ कार्य परिणाम जारी करने का है।

यदि भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो वार्षिक परीक्षा प्रणाली में जुलाई से सत्र प्रारंभ होता था और जून में समाप्त होता था वह सबसे उपयुक्त समय था क्योंकि जून से जुलाई मुख्य रूप से मानसून का मौसम होता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य प्रधानता से होते हैं, इसीलिए कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति काफी कम होती हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। यदि फरवरी मार्च में परीक्षाएं संपादित कर ली जाए और अप्रैल में ही मूल्यांकन कार्य संपन्न हो जाए और जून में परीक्षा परिणाम तैयार करके प्रकाशित कर दिया जाए तो सबको पर्याप्त समय मिलता है और मूल्यांकन भी निरपेक्ष हो पता है इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है, शिक्षण जितना प्रभावशाली होगा उतना ही परिणाम भी प्रभावशाली होगा।

सन्दर्भ सूची

1. सिंह, कर्ण (2017–18) भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवम् इसकी चुनौतियाँ, गोविन्द प्रकाशन, लखीमपुर, खीरी।
2. राय, पारसनाथ और राय, पी.सी (2010–11) अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
3. शर्मा, आर. ए. (2009) *शिक्षा अनुसंधान,* आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
4. गुप्ता, एस. पी. एंड गुप्ता, अल्का (2011) *आधुनिक मापन एवं मूल्याकंन,* शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
5. राष्ट्रीय शिक्षानीति (2020) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. मजूमदार (2010) *सेमेस्टर सिस्टम और वार्षिक प्रणाली के बीच अंतर,* विकास पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली।
7. दुबे, मनीष और दुबे, विभा (2014) अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
8. पांडेय, राम शकल (2008) *शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि,* अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।

——==00==——